



CR
14/7/86

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 1986/ज्येष्ठ 1, 1908

No. 256]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 22, 1986/JYAISTHA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में
रचा जा सके

Separate Pageing is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1986

अधिसूचना

सं. 321/86 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 802(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 40/85—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,

(i) क्रम सं. 18 के सामने स्वयं (3) में "सानक" शब्द के स्थान पर "सानक या लेपित प्रयवर्ध" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) क्रम सं. 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां प्रतः—स्थापित की जाएंगी, अर्थात्—

(1)

(2)

(3)

"19. नूना

यदि उसकी छपत सोडा राख, सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीच लिक्वर के विनिर्माण में उत्पादन कारखाने के भीतर की जाए।

20. प्रक्रिय मैस, संश्लेषण मैस और जिप्सम

यदि उनकी छपत प्रमोनिवा या उर्वरकों के विनिर्माण में उत्पादन कारखाने के भीतर की जाए।

विशेष को आदेश करता है, और ऐसे आदेश का तीन माह की प्रवधि तक अनुपालन नहीं किया जाता है वहाँ अधिकरण ऐसे व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर, अधिनिर्णित रकम की वसूली के लिए या उसके द्वारा मंजूर किए गए किसी अन्य अनुतोष के लिए प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और वह व्यक्ति जिसके पक्ष में ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया जाता, आन्ध्र प्रदेश में आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय को, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उस समय वह राज्य सरकार या संबंधित स्थानीय प्राधिकारी की सेवा कर रहा है या सबसे अंत में सेवा की थी, अधिकरण के आदेश के निष्पादन के लिए आवेदन और ऐसी न्यायालय, तदुपरि, प्रमाणपत्र का उसी रीति से और उसी प्रक्रिया के अनुसार निष्पादन करेगा या कराएगी मानो वह बाद में किसी अधिकरण द्वारा तत्समान अनुतोष के लिए डिक्ली हो।

राष्ट्रपति के आदेश से और उनके नाम से

[एस. 21012/1/80- एस आर]

एस.आर. आर्य, संयुक्त सचिव

टिप्पण :

मूल आदेश सा.का.नि. 285(अ) तारीख 19-5-1975 इसके पूर्व आदेश सा.का.नि. 298(अ) तारीख 23-5-1978 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd May, 1986

ORDER

G.S.R. 805 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (3) and (4) of article 371D of the Constitution, the President hereby makes the following Order further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975, namely :—

1. (1) This Order may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Amendment) Order, 1986.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal Order, 1975,
 - (i) in paragraph 6, for the proviso to sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—
 - “(5) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no interim Order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) shall be made on, or in any proceedings relating to, a representation unless—
 - (a) Copies of such representation and of all documents in support of the plea for such

interim order are furnished to the party against whom such representation is made or proposed to be made ; and

- (b) Opportunity is given to such party to be heard in the matter :

Provided that the Tribunal may dispense with the requirements of clauses (a) and (b) and make an interim order as an exceptional measure if it is satisfied, for reasons to be recorded in writing, that it is necessary so to do for preventing any loss being caused to the representationist, which cannot be adequately compensated in money but any such interim order shall, if it is not sooner vacated, cease to have effect on the expiry of a period of 14 days from the date on which it is made unless the said requirements have been complied with before the expiry of that period and the Tribunal has continued the operation of the interim order” ;

- (ii) in paragraph 7, in sub-paragraph (3), in the first proviso, for the letters and figures “Rs. 300|—” the letters and figures “Rs. 500|—” shall be substituted ;

- (iii) in paragraph 8, after sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

“(5) where the Tribunal makes any order in favour of the person making the representation and against the State Government or the local authority concerned, as the case may be, and such order remains uncomplished with for a period of three months, the Tribunal may, on receipt of an application from such person, issue a certificate for recovery of the amount awarded or, as the case may be, for other relief granted by it, and any person in whose favour such certificate is issued, may apply to the principal Civil Court of Original Jurisdiction in Andhra Pradesh, within the local limits of whose jurisdiction he has, for the time being, been serving or last served the State Government or the local authority concerned, as the case may be, for execution of the order of the Tribunal, and such Court shall thereupon execute the certificate or cause the same to be executed in the same manner and by the same procedure as if it were a decree for like relief made by itself in a suit”.

By order and in the name of the President.

[S-21012/1/80-SR]

S. R. ARYA, Jt. Secy.

NOTE

The Principal Order No. GSR 285 (E) dated 19-05-1975 was earlier amended vide Order No. GSR 298 (E) dated 23-05-1975.

अधिसूचना

सं. 323/86 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 804(घ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 235/86—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं और प्रविष्टियाँ रखी जाएँगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)
"1. कुम कुम		कुछ नहीं "

[फा. सं. बी. 27/27/86—टी आर ए]

गौतम रे, अधीक्षक सचिव

NOTIFICATION

No. 323/86—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 804 (B):— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 235/86—Central Excises, dated the 3rd April, 1986, namely:—

In the Table annexed to the said notification, for Sl. No. 1 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
"1. Kum Kum		Nil".

[F. No. B. 27/27/86—TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy.

